भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2578

4 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

कृषि-जलवायु परिस्थितियों पर आधारित कृषि रूपरेखा

2578. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि-जलवायु परिस्थितियों के आधार पर राज्य-वार कृषि रूपरेखा तैयार करने की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों के साथ आयोजित बैठकों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कृषि रूपरेखा को वर्तमान में तैयार कर रहे या तैयार करने की शुरुआत करने वाले राज्यों की संख्या सहित तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त रूपरेखा को तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय, तकनीकी या संस्थागत सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य-वार ऐसी कृषि रूपरेखा तैयार करने, अंतिम रूप देने और उनके कार्यान्वयन के प्रारंभ के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(च) इस रूपरेखा को तैयार करने में शामिल संस्थागत ढांचे और एजेंसियों तथा स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, जलवायु-अनुकूलता और किसानों की जरूरतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस रूपरेखा के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित अपेक्षित परिणाम और लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार असम, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए कृषि कार्य योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन रोडमैपों को तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से व्यापक परामर्श किया गया है।

आईसीएआर, कृषि और किसान कल्याण विभाग, आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों सहित अन्य संबंधित राज्य विभागों के सहयोग से कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है। यह योजना प्रक्रिया कृषि-जलवायु क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु अनुकूलन क्षमता, तकनीकी उपायों और किसानों की आवश्यकताओं पर आधारित है। इन रोडमैप का मकसद तकनीकी पुष्टि, राज्यों की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल, स्थानीय कृषि-जलवायु स्थितियों और जलवायु के प्रति लचीलेपन को सुनिश्चित करना है।

इस रोडमैप में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता, लाभप्रदता और संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। खेती से जुड़ा यह रोडमैप एक व्यापक नीतिगत ढांचा है जो खेती और मौसम की स्थितियों पर आधारित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग योजनाओं के तहत वार्षिक कार्य योजना बनाते समय इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रख सकते हैं। कृषि रोडमैप के प्रमुख परिणामों में किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि और संबद्ध वस्तुओं में आत्मनिर्भरता में सुधार करना, ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करना और स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों, जलवायु अनुकूलन और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना शामिल है।

*****